भारत सरकार **लोक सभा**

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं. 3685**

वाणिज्य विभाग

दिनांक 12 अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौता

3685. श्री श्यामकुमार दौलत बर्वे:

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने यूरोपीय संघ के साथ प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते पर 12वें दौर की वार्ता पूरी कर ली है;

(ख) यदि हाँ, तो अब तक किन प्रमुख क्षेत्रों के संबंध में सहमति बन पाई है और किन मुद्दों पर अभी भी मतभेद बने हुए है;

(ग) क्या अमेरिका के साथ प्रस्तावित द्विपक्षीय निवेश संधि पर वार्ता निर्धारित समय तक पूरी होने की संभावना यदि हाँ, तो इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(घ) क्या आसियान के साथ भारत के मौजूदा मुक्त व्यापार समझौते की समीक्षा प्रक्रिया संतोषजनक रही है, यदि हाँ, तो अब तक कितने दौर की वार्ता हुई है और किन मुद्दों पर आम सहमति बनी है; और

(ङ) क्या अमेरिका द्वारा इस्पात, ऑटो और संबंधित क्षेत्रों पर 25 से 50 प्रतिशत तक टैरिफ लगाए जाने से भारतीय निर्यातकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है, यदि हाँ, तो इन प्रभावों को कम करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क) और (ख) भारत और यूरोपीय संघ (ईयू) ने जून 2022 में मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर वार्ता फिर से शुरू की। 12वें दौर की वार्ता दिनांक 7 से 11 जुलाई, 2025 तक ब्रुसेल्स में आयोजित हुई। आर्थिक साझेदारी को बढ़ावा देने, बाज़ार पहुँच बढ़ाने और नियम-आधारित सहयोग को मज़बूत करने के उद्देश्य से विभिन्न स्तरों पर चर्चाएँ आगे बढ़ रही हैं। इस प्रक्रिया का उद्देश्य एक निष्पक्ष, संतुलित और पारस्परिक रूप से लाभकारी मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देना है।

(ग) भारत-अमेरिका बीटीए वार्ता मार्च 2025 में शुरू की गई थी और वार्ता के पांच दौर आयोजित किए गए हैं, अंतिम वार्ता 14-18 जुलाई 2025 को वाशिंगटन, अमेरिका में आयोजित हुई थी।

(घ) भारत और आसियान, आसियान-भारत वस्तु व्यापार समझौते (एआईटीआईजीए) की समीक्षा पर रचनात्मक रूप से नियोजित हैं जिस पर वर्ष 2009 में हस्ताक्षर हुए थे और अभी तक, एआईटीआईजीए संयुक्त समिति की 9 बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं।

(ङ.) विभिन्न क्षेत्रों में अमेरिका को होने वाले निर्यात पर अमेरिकी टैरिफ का प्रभाव प्रतिस्पर्धी देशों सहित अन्य देशों पर लागू तुलनात्मक टैरिफ के आधार पर निर्भर करेगा और अलग-अलग होगा। वाणिज्य विभाग निर्यात संवर्धन और विविधीकरण उपायों के माध्यम से इस प्रभाव को कम करने में मदद के लिए हितधारकों के साथ मिलकर कार्य कर रहा है।

*****